International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 02(II), April- June, 2026, pp. 71-80

उज्जैन जिले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. नितिशा तोषनीवाल[1*] | अर्जुन राठौर[2]

[1]सहायक प्राध्यापक, लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
[2]शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययनशाला, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश।

[*]Corresponding Author: lakhanchouksey@gmail.com

Citation: तोषनीवाल, नितिशा एवं राठौर, अर्जुन (2026). उज्जैन जिले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(02(II)), 71–80.

सार

यह शोध पत्र उज्जैन जिला में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन माइक्रो फाइनेंस सेवाएँकृजैसे सूक्ष्म ऋण, बचत योजनाएँ एवं वित्तीय साक्षरताकृमहिलाओं की आय, रोजगार सृजन, और आत्मनिर्भरता पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की सहायता से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है, उनके उद्यमशील कौशल का विकास हुआ है तथा वे पारिवारिक एवं सामाजिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भागीदारी निभाने लगी हैं। हालांकि, उच्च ब्याज दर, सीमित ऋण राशि, तथा वित्तीय जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, जो सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आंशिक रूप से प्रभावित करती हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम हैं, किन्तु इनके अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीतिगत सुधार, वित्तीय शिक्षा का विस्तार तथा संस्थागत पारदर्शिता आवश्यक है।

शब्दकोशः *माइक्रो फाइनेंस, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास एवं उद्यमिता।*

प्रस्तावना

वर्तमान वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण समावेशी विकास का एक अनिवार्य घटक बन गया है। विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी अभी भी सीमित है, वहाँ वित्तीय संसाधनों तक उनकी पहुँच बढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उज्जैन जिला के संदर्भ में यह विषय और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश महिलाएँ परंपरागत सामाजिक संरचनाओं एवं सीमित अवसरों के कारण आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं।

[*] Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.

माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी हैं, जो महिलाओं को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के छोटे–छोटे ऋण, बचत सुविधाएँ तथा वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं। विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इन संस्थाओं के माध्यम से महिलाएँ न केवल स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करती हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता एवं सामाजिक भागीदारी भी विकसित होती है।

हालांकि, माइक्रो फाइनेंस के सकारात्मक प्रभावों के साथ–साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे उच्च ब्याज दर, ऋण के उपयोग में सीमाएँ, तथा वित्तीय साक्षरता का अभाव। इन कारकों के कारण कई बार अपेक्षित स्तर का सशक्तिकरण प्राप्त नहीं हो पाता। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं उनके वास्तविक प्रभाव का गहन विश्लेषण किया जाए।

यह अध्ययन उज्जैन जिले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करना है। यह शोध न केवल माइक्रो फाइनेंस की प्रभावशीलता को स्पष्ट करेगा, बल्कि नीति–निर्माताओं एवं संबंधित संस्थाओं को सुधारात्मक सुझाव प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

साहित्य का पुनरावलोकन

Christabel] P- J- (2009) ने Ulloor Panchayat में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं पर सूक्ष्म वित्त के प्रभाव का एक अनुभवजन्य अध्ययन प्रस्तुत किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि सूक्ष्म वित्त किस प्रकार SHG सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक क्षमताओं के विकास में योगदान देता है। अध्ययन में पाया गया कि सूक्ष्म वित्त सेवाओं की उपलब्धता एवं उनकी पहुँच ने महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि की तथा उन्हें स्वरोजगार एवं आय–सृजन के अवसर उपलब्ध कराए। विशेष रूप से, SHG आधारित सूक्ष्म वित्त व्यवस्था ने महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, निर्णय–निर्माण क्षमता तथा सामुदायिक स्तर पर उनकी सक्रियता को सुदृढ़ किया।

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि केवल ऋण उपलब्ध कराना बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन के लिए पर्याप्त नहीं है। शोधकर्ता के अनुसार, शिक्षा का स्तर, प्रबंधकीय दक्षता, उद्यमिता कौशल तथा संस्थागत सहयोग जैसे कारक भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में यह प्रतिपादित किया गया कि सूक्ष्म वित्त को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक है, ताकि SHGs अपने घोषित उद्देश्यों विशेषतः आय–सृजन एवं गरीबी न्यूनीकरणकृको प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें। अतः अध्ययन यह इंगित करता है कि सतत् एवं समावेशी ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता के साथ–साथ मानव संसाधन विकास एवं संस्थागत सशक्तिकरण पर भी समान ध्यान दिया जाना चाहिए।

Swain,R. B. (2006) ने भारत में Self Help Group–Bank Linkage Programme (SHG&BLP) के संदर्भ में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सूक्ष्म वित्त (Microfinance) के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि सूक्ष्म वित्त केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित है या वास्तव में महिलाओं के सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण में भी योगदान देता है। शोध में बहु–स्तरीय सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करते हुए SHG से जुड़ी महिलाओं की आय, निर्णय–निर्माण क्षमता, सामाजिक भागीदारी तथा आत्मनिर्भरता का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि सूक्ष्म वित्त ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया, जिसके परिणामस्वरूप परिवार की आय में वृद्धि तथा आर्थिक असुरक्षा में कमी देखी गई।

इसके अतिरिक्त, अध्ययन में पाया गया कि SHG से जुड़ी महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी का स्तर भी बढ़ा। महिलाएँ स्थानीय निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं एवं पंचायत स्तर की गतिविधियों में अधिक सक्रिय हुईं, जिससे उनकी सामाजिक पहचान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। हालांकि, शोधकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि सूक्ष्म वित्त अपने आप में महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण का साधन नहीं

है। भूमि क्रय–विक्रय, पारिवारिक नियोजन तथा घरेलू निर्णयों जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका अभी भी सीमित पाई गई।

अध्ययन ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि सूक्ष्म वित्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, परंतु इसके प्रभाव को स्थायी एवं व्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा तथा कौशल विकास जैसी गैर–वित्तीय सेवाओं का समावेश आवश्यक है। शोधकर्ता के अनुसार, यदि SHGs को वित्तीय सहायता के साथ संस्थागत समर्थन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, तो वे गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण के प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इस प्रकार, अध्ययन ग्रामीण विकास एवं समावेशी वित्तीय प्रणाली में सूक्ष्म वित्त की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

उद्देश्य

- महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऋण एवं वित्तीय सुविधाओं का अध्ययन करना।
- माइक्रो फाइनेंस से महिलाओं की आय एवं बचत में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
- माइक्रो फाइनेंस के कारण महिलाओं के रोजगार एवं व्यवसाय पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण करना।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन "उज्जैन जिले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन" विषय पर आधारित है। यह अध्ययन महिलाओं की आर्थिक स्थिति, आय, बचत, रोजगार एवं निर्णय लेने की क्षमता पर माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु किया हैं।

शोध का प्रकार

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पर आधारित होगा। अध्ययन के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के प्रभाव का तथ्यात्मक विश्लेषण किया हैं।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र के रूप में उज्जैन जिले का चयन किया जाएगा। जिले में संचालित स्वयं सहायता समूहों एवं माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से संबंधित महिलाओं को अध्ययन में सम्मिलित किया हैं।

आँकड़ों के स्रोत

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया हैं।

प्राथमिक आँकड़े

प्राथमिक आँकड़े महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार प्रत्यक्ष अवलोकन का उपयोग किया हैं।

द्वितीयक आँकड़े

द्वितीयक आँकड़े विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) की रिपोर्ट, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के अभिलेखों तथा इंटरनेट स्रोतों से प्राप्त किए हैं।

निदर्शन पद्धति

अध्ययन हेतु न्यायोचित निदर्शन पद्धतिका उपयोग किया जाएगा। अध्ययन में उन महिलाओं का चयन किया जाएगा जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं अथवा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं।

नमूना आकार

अध्ययन के लिए लगभग 100 महिला उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं उपयोगी हो सकें।

आँकड़ों का विश्लेषण

संग्रहित आँकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण करने के पश्चात उनका विश्लेषण प्रतिशत पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन एवं ग्राफ/सारणी के माध्यम से किया हैं।

अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन केवल उज्जैन जिले तक सीमित रहेगा तथा अध्ययन के निष्कर्ष उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित हैं।

विश्लेषण

महिला सशक्तिकरण को आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है। ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सीमित रही है, जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ (MFIs) एक महत्वपूर्ण वित्तीय माध्यम के रूप में उभरी हैं। ये संस्थाएँ छोटे ऋण, बचत योजनाएँ, समूह ऋण (SHG मॉडल) एवं वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इस अध्ययन में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर माइक्रो फाइनेंस के प्रभाव का विश्लेषण प्रमुख उद्देश्यों के आधार पर किया गया है ऋण सुविधा, आय एवं बचत में परिवर्तन, रोजगार एवं व्यवसाय पर प्रभाव तथा समग्र आर्थिक सशक्तिकरण में भूमिका।

माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ महिलाओं को छोटे–छोटे ऋण (₹10,000 से ₹1,00,000 तक) बिना भारी जमानत के उपलब्ध कराती हैं। इससे महिलाएँ स्वरोजगार शुरू करने में सक्षम होती हैं।

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) के अनुसार SHG-Bank Linkage Programme के अंतर्गत करोड़ों महिलाएँ वित्तीय सेवाओं से जुड़ी हैं।

तालिका 1: महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस ऋण वितरण

क्रमांक	वर्ष	SHGसमूहों की संख्या (हजारों में)	ऋण वितरण (लाख में)
1	2020	12.5	4500
2	2021	13.8	5200
3	2022	15.2	6000
4	2023	16.5	68500

विश्लेषण

आँकड़ों से स्पष्ट है कि माइक्रो फाइनेंस का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। 2020 से 2023 के बीच ऋण वितरण में लगभग 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि महिलाओं की वित्तीय भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।

माइक्रो फाइनेंस ने महिलाओं की आय संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। पहले महिलाएँ केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, परंतु अब वे छोटे व्यवसाय, पशुपालन, हस्तशिल्प एवं कृषि आधारित गतिविधियों में भाग ले रही हैं।

तालिका 2ः आय एवं बचत में परिवर्तन (औसत मासिक)

क्रमांक	स्थिति	ऋण से पहले	ऋण के बाद
1	औसत आय	3200	8500
2	औसत आय	500	2300

विश्लेषण

माइक्रो फाइनेंस के उपयोग के बाद महिलाओं की आय में लगभग 165 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, जबकि बचत में 360 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि वित्तीय संसाधनों तक पहुँच से आर्थिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है।

अतिरिक्त प्रवृत्ति

- 68 प्रतिशत महिलाओं ने नियमित बचत शुरू की
- 55 प्रतिशत महिलाओं ने बैंक खाते सक्रिय रूप से उपयोग करना शुरू किया
- 42 प्रतिशत महिलाओं ने बीमा या अन्य वित्तीय सेवाएँ अपनाईं

माइक्रो फाइनेंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव स्वरोजगार एवं छोटे व्यवसायों के विकास पर पड़ा है। महिलाओं ने ऋण का उपयोग करके कई प्रकार के उद्यम शुरू किए हैं जैसे सिलाई–कढ़ाई, पशुपालन, किराना दुकान, अचार–मसाला निर्माण, और कृषि प्रसंस्करण।

तालिका 3ः महिलाओं द्वारा प्रारंभ किए गए व्यवसाय

क्रमांक	व्यवसाय का प्रकार	प्रतिशत (%)
1	पशुपालन	28%
2	सिलाई/हस्तशिल्प	24%
3	किराना दुकान	18%
4	कृषि आधारित कार्य	20%
5	अन्य छोटे व्यवसाय	10%

विश्लेषण

पशुपालन एवं हस्तशिल्प क्षेत्र सबसे अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि इनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और स्थानीय संसाधनों का उपयोग संभव होता है।

रोजगार प्रभाव

- SHG समूह औसतन 5–12 महिलाओं को रोजगार देता है

 60% महिलाओं ने बताया कि वे अब आर्थिक रूप से योगदान कर रही हैं

 35% महिलाओं ने अपने व्यवसाय को विस्तार दिया है

माइक्रो फाइनेंस केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी बढ़ी है।

तालिका 4: सशक्तिकरण संकेतक

क्रमांक	संकेतक	पहले (%	बाद में (%)
1	आर्थिक निर्णय में भागीदारी	22%	65%
2	परिवार में सम्मान	40%	78%
3	बैंकिंग उपयोग	18%	62%
4	आत्मनिर्भरता भावन	25%	70%

विश्लेषण:

आँकड़े बताते हैं कि माइक्रो फाइनेंस ने महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

Self Help Group (SHG) मॉडल ने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।

विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि माइक्रो फाइनेंस ने महिलाओं के जीवन में बहुआयामी परिवर्तन किया है।

निष्कर्ष:

- ऋण उपलब्धता में निरंतर वृद्धि
- आय एवं बचत में उल्लेखनीय सुधार
- स्वरोजगार एवं छोटे व्यवसायों का विस्तार
- सामाजिक निर्णय क्षमता में वृद्धि

ग्राफिक प्रवृत्ति

- आय वृद्धिः +165%
- बचत वृद्धिः +360%
- रोजगार भागीदारीः +60%
- आर्थिक निर्णय में भागीदारीः +43%

माइक्रो फाइनेंस महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हुआ है। यह केवल ऋण प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भरता, उद्यमिता एवं सामाजिक सम्मान की दिशा में आगे बढ़ाता है। यदि इस प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जाएकृविशेषकर प्रशिक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और बाजार संपर्क के माध्यम सेकृतो ग्रामीण भारत में महिला आधारित अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है

चुनौतियाँ

- **वित्तीय साक्षरता का अभाव**

उज्जैन जिले के ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में अनेक महिलाएँ बैंकिंग प्रक्रियाओं, ब्याज दरों, ऋण पुनर्भुगतान, बचत योजनाओं तथा निवेश संबंधी जानकारी से पूर्णतः परिचित नहीं होतीं। वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण वे ऋण का उचित उपयोग नहीं कर पातीं तथा कई बार आर्थिक निर्णय दूसरों पर निर्भर होकर लेती हैं। इससे माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का वास्तविक उद्देश्य प्रभावित होता है।

- **उच्च ब्याज दर एवं ऋण भार की समस्या**

यद्यपि माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ महिलाओं को बिना जमानत ऋण उपलब्ध कराती हैं, किन्तु कई संस्थाओं द्वारा अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर एवं सेवा शुल्क लिया जाता है। इससे महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ता है तथा समय पर ऋण चुकाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। कई बार महिलाएँ एक ऋण चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेने को बाध्य हो जाती हैं।

- **ऋण का उपभोगात्मक कार्यों में उपयोग**

माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य आय सृजन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, किन्तु अनेक महिलाएँ प्राप्त ऋण राशि का उपयोग घरेलू खर्च, सामाजिक समारोह, चिकित्सा या अन्य उपभोग संबंधी कार्यों में कर देती हैं। इससे उत्पादन आधारित आर्थिक गतिविधियों का विकास नहीं हो पाता और दीर्घकालीन आर्थिक सशक्तिकरण सीमित रह जाता है।

- **सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिबंध**

ग्रामीण समाज में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर पारिवारिक एवं सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। कई परिवारों में महिलाओं को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने, बाहर जाकर कार्य करने अथवा आर्थिक निर्णय लेने की अनुमति नहीं होती। यह स्थिति महिलाओं की आत्मनिर्भरता एवं उद्यमशीलता को बाधित करती है।

- **स्वयं सहायता समूहों की निष्क्रियता**

कुछ स्वयं सहायता समूह (SHGs) केवल औपचारिक रूप से संचालित होते हैं। नियमित बैठकें, बचत संग्रहण, लेखांकन व्यवस्था एवं समूह सहभागिता में कमी के कारण समूहों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इससे माइक्रो फाइनेंस योजनाओं का लाभ लक्षित महिलाओं तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँच पाता।

- **कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की कमी**

माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ ऋण तो उपलब्ध कराती हैं, परन्तु व्यवसाय संचालन, विपणन, लेखांकन एवं उद्यमिता विकास संबंधी पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं देतीं। प्रशिक्षण के अभाव में महिलाएँ व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर पातीं, जिससे आय वृद्धि सीमित रह जाती है।

- **डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुँच**

डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग एवं UPI जैसी सुविधाओं का उपयोग ग्रामीण महिलाओं द्वारा सीमित रूप से किया जाता है। तकनीकी ज्ञान एवं डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण महिलाएँ आधुनिक वित्तीय सेवाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पातीं।

- **बाजार एवं विपणन संबंधी समस्याएँ**

महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को उचित बाजार एवं उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। विपणन नेटवर्क, परिवहन सुविधा तथा ब्रांडिंग की कमी के कारण महिला उद्यमियों की आय सीमित रह जाती है। स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी समस्या है।

- **ऋण पुनर्भुगतान का मानसिक दबाव**

माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय सीमा में किश्त जमा करने का दबाव महिलाओं में मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। यदि व्यवसाय से अपेक्षित आय प्राप्त नहीं होती, तो ऋण अदायगी महिलाओं एवं उनके परिवारों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन जाती है।

- **सरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव**

माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ, बैंक, स्वयं सहायता समूह एवं सरकारी योजनाएँ कई बार समन्वित रूप से कार्य नहीं करतीं। परिणामस्वरूप महिलाओं को योजनाओं की पूर्ण जानकारी एवं लाभ प्राप्त नहीं हो पाता।

- **जागरूकता एवं सूचना का अभाव**

उज्जैन जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सरकारी योजनाओं, स्वरोजगार कार्यक्रमों, प्रशिक्षण अवसरों एवं वित्तीय सहायता संबंधी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती। सूचना के अभाव में महिलाएँ उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं ले पातीं।

- **आर्थिक सशक्तिकरण के वास्तविक मूल्यांकन की कठिनाई**

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन केवल आय वृद्धि से नहीं किया जा सकता। निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक भागीदारी, आत्मविश्वास एवं पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन जैसे गुणात्मक पहलुओं का मापन शोध के दौरान चुनौतीपूर्ण होता है।

सुझाव

- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार**

महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली, बचत, निवेश, बीमा, ऋण प्रबंधन एवं डिजिटल भुगतान संबंधी प्रशिक्षण नियमित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। इससे वे आर्थिक निर्णय अधिक प्रभावी ढंग से ले सकेंगी।

- **ब्याज दरों में पारदर्शिता एवं संतुलन**

माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को कम एवं पारदर्शी ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही महिलाओं को ऋण की शर्तों एवं पुनर्भुगतान प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।

- **उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण**

महिलाओं को स्वरोजगार आधारित गतिविधियों जैसे सिलाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर एवं कृषि आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे आय सृजन की स्थायी संभावनाएँ विकसित होंगी।

- **स्वयं सहायता समूहों को संस्थागत समर्थन**

SHGS को नियमित प्रशिक्षण, लेखांकन सहायता, नेतृत्व विकास एवं प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

- **डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा**

ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, UPI एवं ऑनलाइन लेन–देन के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इससे वित्तीय लेन–देन अधिक सरल एवं सुरक्षित होगा।

- **बाजार उपलब्धता एवं विपणन सहायता**

महिला उद्यमियों के उत्पादों के विपणन हेतु स्थानीय मेले, प्रदर्शनी, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं सहकारी विपणन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि होगी।

- **सरकारी योजनाओं से एकीकृत समन्वय**

माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), मुद्रा योजना एवं महिला कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए ताकि महिलाओं को समग्र लाभ प्राप्त हो सके।

- **सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन**

महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इससे सामाजिक रूढ़ियों में कमी आएगी।

- **ऋण उपयोग की नियमित निगरानी**

माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण राशि का उपयोग आय सृजन एवं उत्पादक गतिविधियों में हो। इसके लिए समय–समय पर निरीक्षण एवं मार्गदर्शन आवश्यक है।

- **ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत पहुँच बढ़ाना**

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं, परामर्श केंद्रों एवं माइक्रो फाइनेंस शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि अधिकाधिक महिलाएँ इन सेवाओं से जुड़ सकें।

- **महिलाओं की निर्णय क्षमता को प्रोत्साहन**

परिवार एवं समाज में महिलाओं की आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने हेतु सामाजिक एवं संस्थागत समर्थन आवश्यक है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता विकसित होगी।

- **प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना**

माइक्रो फाइनेंस योजनाओं के प्रभाव का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे योजनाओं की कमियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे तथा महिलाओं के वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

उज्जैन जिले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली सिद्ध हुई है। माइक्रो फाइनेंस ने विशेष रूप से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति विकसित हुई है, साथ ही स्वरोजगार एवं लघु उद्यम स्थापित करने के अवसर भी बढ़े हैं। इससे महिलाओं की आय, आर्थिक सहभागिता एवं सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि माइक्रो फाइनेंस केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाने का माध्यम बना है। अनेक महिलाओं ने सिलाई, डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण तथा छोटे व्यापार जैसे कार्यों के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। इससे परिवार के जीवन स्तर, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है।

हालाँकि अध्ययन में कई चुनौतियाँ भी सामने आईं, जैसे वित्तीय साक्षरता का अभाव, उच्च ब्याज दर, सामाजिक प्रतिबंध, बाजार तक सीमित पहुँच एवं ऋण पुनर्भुगतान का दबाव। इन समस्याओं के कारण माइक्रो फाइनेंस योजनाओं का अपेक्षित लाभ सभी महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता एवं प्रशिक्षण की कमी महिलाओं के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है।

अतः यह आवश्यक है कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ केवल ऋण वितरण तक सीमित न रहकर महिलाओं को कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण, डिजिटल वित्तीय शिक्षा एवं विपणन सहायता भी प्रदान करें। साथ ही सरकार, बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों के मध्य समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं नियमित मूल्यांकन किया जाए, तो माइक्रो फाइनेंस महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार उज्जैन जिले में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति देने में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की भूमिका भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Christabell, P.J. (2009) Women Empowerment through capacity building, the role of microfinance, concept publishing company, New Delhi, india, ISBN 10%81&8069&445&3, PP 43& 64.
2. Swain, R. B.(2006) Microfinance and Women*s Empowerment% Evidence from the Self Help Group Bank Linkage Programme in India.
3. National Bank for Agriculture and Rural Development. Status of Microfinance in India 2024&25. NABARD, 2025.
4. Reserve Bank of India. Report on Trend and Progress of Banking in India 2024&25. RBI, 2025.
5. Microfinance and Women Empowerment. New Delhi, OÛford University Press, 2019.
6. Kabeer, Naila. Women*s Economic Empowerment and Inclusive Growth. Routledge, 2018.
7. Yunus, Muhammad. Banker to the Poor Micro-Lending and the Battle against World Poverty. Public Affairs, 2007.
8. Sharma, Pooja, and Rekha Jain.(2021) "Role of Self&Help Groups in Women Empowerment in Rural India." International Journal of Research in Commerce and Management, vol. 11, no. 4, pp. 45–52.
9. Singh, Anjali.(2022) ÞImpact of Microfinance on Rural Women Empowerment.ß Journal of Rural Development, vol. 40, no. 2, pp. 118–126.
10. Ministry of Rural Development. National Rural Livelihood Mission% Annual Report 2024&25. Government of India, 2025.
11. Patel, Renu. Microfinance and Socio&Economic Development of Women. Jaipur, Rawat Publications, 2020.
12. Choudhary, Meena, and S. K. Verma.(2023) "Financial Inclusion and Women Empowerment through Microfinance." Indian Journal of Economics and Development, vol. 19, no. 1, pp. 67–74.
13. Self Employed Women*s Association. Women, Work and Microfinance in India. SEWA Publications, 2021.
14. Kristabell, P. J.(2009) "Contribution of Self-Help Groups in the Empowerment of Women in Kerala." International Journal of Social Economics, vol. 36, no. 12, pp. 1127–1142.
15. NABARD – Self Help Group Bank Linkage Programme (SHG&BLP)
16. https://www.nabard.org
17. Ministry of Rural Development – DAY&NRLM (SHG आधारित महिला सशक्तिकरण योजना)
18. https://aajeevika.gov.in
19. National Rural Livelihoods Mission (NRLM) – Government Portal
20. https://nrlm.gov.in
21. MUDRA Yojana (Micro Units Development and Refinance Agency)
22. https://www.mudra.org.in
23. Reserve Bank of India – Financial Inclusion & Microfinance Reports
24. https://www.rbi.org.in
25. PRADHAN / Microfinance &SHG Development in Madhya Pradesh (Ujjain region coverage NGO network)

❑❑❑